

# हरिजनसेवक

दो आना

(संस्थापक : महात्मा गांधी)

भाग १९

सम्पादक : मगनभाई प्रभुदास देसाई

अंक ३९

मुद्रक और प्रकाशक  
जीवणजी डाह्याभाभी देसायी  
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद-१४

अहमदाबाद, शनिवार, ता० २६ नवम्बर, १९५५

वार्षिक मूल्य : देशमें ६०/-  
विदेशमें ६०/-; शि० १४

## भारतका समाजशास्त्र

[ता० २८-९-५५ को कुजेन्द्री (अुत्कल) में दिया गया प्रार्थना-प्रवचन।]

कार्यकर्ताओंके बारेमें कुछ चिंतन करके दो विचार अुपस्थित किये गये हैं। कहा गया है कि जिन परिवारोंमें दो-चार भाओं होते हैं, उनमें से अेकाध भाओंको सार्वजनिक सेवाके लिये छोड़ें, अुसकी आजीविका और परिवार आदिका जिम्मा वे अुठाएँ और निष्काम भावसे अेक भाओं सेवा करता रहे। दूसरी बात यह सुझायी गयी कि कुछ वानप्रस्थ वृत्तिके लोग हों। जैसे आज यहां पर चंद लोग हैं, वैसे जगह-जगह निर्माण हों और अुनका आकर्षण जनसेवाकी तरफ हो। वैसे ये दोनों सूचनाएँ अिन चार-पांच सालके मेरे प्रवासके दरमियान ही मेरे सामने नहीं आयीं, बल्कि अुसके पहले भी वर्षोंसे मैं यह कहते आया हूं।

### संयुक्त परिवारका लाभ

दिन-ब-दिन जिसे हम सामूहिक या संयुक्त परिवार कहते हैं वे टूट रहे हैं, जो हमारी समाज-रचना पर अेक आपत्ति है। अुसके कारणोंमें मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन मुख्य कारण है—समाजकी अर्थमूलक रचना। अिसके कारण परिवारके लोग पैसेकी शोधमें अनेक धंजोंमें लग जाते हैं और अनेक स्थानोंमें बंट जाते हैं। जो अेक स्थानमें रहते हैं, अुनका भी आपस-आपसमें मेल नहीं रहता। अिसलिये घरके टुकड़े हो जाते हैं। आज जमीनके 'सीलिंग' की जो बात चलती है, अुसके कारण कुटुम्ब संस्थाके भंगके वास्ते और भी अधिक चालना मिलती है। अिस बारेमें मैंने बिहारमें कभी जगह लोगोंको आगाह किया कि भाअियो, अिससे बचो। अिसमें कोअी संदेह नहीं है कि अगर सामूहिक परिवार बने रहेंगे, तो हरअेक परिवारकी तरफसे अेक सार्वजनिक कार्यकर्ताका दान हो सकता है। हमें अेक दफा यात्रामें राष्ट्रपतिजीसे मिलनेका मौका मिला। अुनके साथ अिस विषयमें चर्चा अुठी। मैंने अुनके सामने संयुक्त परिवारकी अुपयोगिता अुपस्थित की, तो वे कहने लगे कि यह तो मेरे ही अनुभवसे सिद्ध होता है। अगर हमारा सामूहिक परिवार नहीं होता और हमारे दूसरे भाओं हमारी चिंता नहीं करते तो शायद मैं सार्वजनिक सेवाके लिये अुपलब्ध नहीं होता। अुन्होंने अपना यह जो अनुभव बताया वह बहुत ही ध्यानमें लेने लायक है।

### नये युगकी सौगात

वानप्रस्थ आश्रमकी बात हमारे लिये और हमारी संस्कृतिके लिये नयी नहीं है। लेकिन आज हमारे पास अपनी संस्कृतिका केवल अभिमानमात्र रहा है, अुसका कोअी स्वरूप मौजूद नहीं है। हमारी समाज-रचनाके जो मूलभूत तत्व थे, वे सारे दिन-ब-दिन टूट रहे हैं। अिस भूमिमें समाजशास्त्रका गहरा चिंतन वर्षोंसे बंद

है। दूसरे कुछ विषयोंका चिंतन जरूर चला है। अर्थशास्त्रीय कुछ चिंतन हुआ है। और राजनीतिशास्त्रका भी कुछ चिंतन हुआ है, किन्तु अपनी स्थितिको ध्यानमें रखकर समाजशास्त्रका मूलभूत चिंतन अिन दिनों हुआ ही नहीं। जिसे हम समाजशास्त्रका चिंतन कहते हैं अुसका अिन दो सौ सालमें बहुत ही कम चिंतन हुआ है। बल्कि जो कुछ थोड़ीसी कोशिश अुठी है, वह यहांके समाजको तोड़नेकी ही अुठी है। जानबूझकर समाज तोड़नेकी कोशिश अुठी है, अैसी बात नहीं। परन्तु पश्चिमका समाजशास्त्र श्रद्धापूर्वक ग्रहण करके यहां लागू करनेकी चेष्टा की गयी। हमारी आश्रम-व्यवस्था कितनी व्यापक, कितनी सूक्ष्म और कितनी गहरी थी अिसका दर्शन हमें नहीं हुआ।

### आश्रम-व्यवस्थाका मूल

हमारी आश्रम-व्यवस्थामें अुत्तम मानसशास्त्र, अुत्तम शिक्षण-शास्त्र और अुत्तम विचारशास्त्र तीनों अिकटूठे अुठे हैं। मानस और विचार, दोनोंके बारेमें सोचते अुठे मानव-जीवनके दो बड़े हिस्से होते हैं। अेक होता है प्रवृत्ति-विभाग और दूसरा होता है निवृत्ति-विभाग। दोनों विरोधी नहीं हैं, दोनों परस्पर पूरक हैं। किसीके जीवनमें किसी चीजकी प्रधानता या अधिकता हो सकती है। परन्तु दोनोंकी आवश्यकता हरअेकके जीवनमें होती है और दोनों मिलकर पूर्णता होती है। प्रवृत्तिका अर्थ था—कर्मयोग-मूलक अभ्युदयका प्रयत्न। समाज अुन्नत हो, अुसका जीवन-मान या जीवनका स्तर समान रूपसे अूँचा अुठे अिसकी कोशिश। सूत्रमें कहना हो तो अुसे कहेंगे कर्मयोग-मूलक जनसेवा। साधारण-तया हरअेकके जीवनका पूर्वार्ध अिस प्रकारका होना चाहिये और जीवनका अुत्तरार्ध निवृत्तिके लिये होना चाहिये। निवृत्ति चिंतन-प्रधान होती है और अुसका हेतु है लोक-शिक्षण। अगर हम यह कहें कि अभ्युदयका अर्थ है लोगोंका जीवनस्तर अूँचा अुठाना, तो निवृत्तिका अर्थ होता है लोगोंका चिंतनस्तर अूँचा अुठाना। समाजकी स्थूल अुन्नतिके सारे कार्य कर्मयोगके जरिये होते हैं और समाजकी सूक्ष्म अुन्नतिके सारे कार्य चिंतनसे होते हैं।

### भगवान् बुद्ध और कृषिकार्य

कर्मयोगमें कृषि प्रधान होती है, अिसलिये मैंने आग्रह रखा है कि हरअेकको खेतीमें हिस्सा लेना चाहिये। अिसके लिये मैं अपने पूर्वजोंके वचनोंका आधार दे सकता हूं। लेकिन वह दिये बिना ही यह कह रहा हूं कि खेतीके बिना व्यक्तित्व कभी पूर्ण नहीं होगा। जब बुद्ध भगवान्से पूछा गया कि आप खेती क्यों नहीं करते हैं, तो अुन्होंने यह जवाब नहीं दिया कि भाओं, खेती तो तुम्हारे लिये है, मेरे लिये नहीं। अुन्होंने कहा कि मेरे लिये लोक-मानसकी विशाल भूमि है और प्रबोध-शक्ति ही मेरा हल है, प्रेमरूपी पानीका प्रवाह मैं अुसमें छोड़ता हूं, अित्यादि अित्यादि।

जैसे कोबी किसान बताता है, उस तरह अन्होंने सांगोपांग और सुन्दर वर्णन बताया। और जब शिष्यकी तरफसे अन्हें पूछा गया कि आप हमारे लिये क्या प्रत्यक्ष कार्यक्रम देंगे, तो अन्होंने कहा, मैं ऐसा कार्यक्रम पेश कर रहा हूँ जिसमें तुम्हारा आरोग्य भी सधेगा और तुम्हारी अन्नति भी सधेगी। वे बोले, अखंड घूमा करो और तालाब खोदा करो। मैंने यह चीज आपके सामने अिसलिये रखी कि मनुष्य-जीवनमें कृषि अनिवार्य है, उसके बिना ब्यक्तिकी पूर्णता नहीं होती है, अिसका निदर्शन आपको मिले। कृषिके साथ-साथ दूसरे विविध व्यवसाय भी हो सकते हैं, वे कृषिके साथ ही शोभा देते हैं। अिस तरह कर्मयोगकी अवस्थामें हरअेकके जीवनमें कृषिका अंग होना चाहिये।

### अनुभवी लोगोंका शिक्षण-कार्य

हरअेकको अपने अुत्तर जीवनमें अध्यापक होना चाहिये और शिक्षणका काम करना चाहिये। मैंने कहा था कि हम विद्यार्थियोंको शिक्षा देना चाहते हैं। तो अैसे ही शिक्षकोंके जरिये शिक्षण देना योग्य होगा, जो कि कुछ अनुभवी हों। आज तो नये-नये, बिना अनुभवके जवानोंको अध्यापक बनाया जाता है। जिन्होंने जीवनमें कुछ पुरुषार्थ नहीं किया है वे तालीमका काम करते हैं। कोबी वाणिज्य-विद्या सिखाते हैं, परन्तु अन्होंने व्यापार नहीं किया है। जो लश्करकी विद्या सिखाते हैं, अन्होंने लश्करमें कोबी पराक्रम नहीं किया है। और राजनीति पर तो हर कॉलेजमें व्याख्यान होते हैं, अैसे लोगों द्वारा जिन्होंने पॉलिटिक्समें कोबी हिस्सा नहीं लिया। तत्त्वज्ञानकी व्याख्या तो हर कॉलेजमें होती है, यद्यपि अर्थकी माया किसीकी छुटी नहीं है। व्याख्याताकी भी नहीं। अिसलिये हमारी योजनामें घनश्यामदास बिडलाके लिये यह लाजमी है कि अेक अुन्नमें अपना व्यापार छोड़कर वे हमारे विद्यालयमें अध्यापक बनें। पंडित नेहरूके लिये यह लाजमी है कि वे अेक अवस्थामें प्रधानमंत्री-पद छोड़कर हमारे विद्यालयमें पॉलिटिक्स (राजनीति)के अध्यापक बनें। मेरे कहनेका मतलब यह है कि अूंचेसे अूंचे अनुभवी लोगोंको अपनी अेक अुन्नमें शिक्षण-कार्यमें हिस्सा लेना चाहिये।

अिस तरह प्रवृत्ति-विभाग और निवृत्ति-विभाग मिलकर जीवन पूर्ण होता है, अैसी कल्पना की गयी। ये दोनों विभाग अितने प्राकृतिक हैं कि आज भी हरअेकके जीवनमें वे होते हैं, लेकिन विकृत रूपमें होते हैं। आज हमारी प्रवृत्ति लोक-सेवा-परायण कर्मयोगकी न रहकर विषय-सेवा-परायण है। आज हमारी निवृत्ति चिंतन-परायण या शिक्षण-परायण न होकर आराम या निष्क्रियता-परायण हो गयी है। हम अितना ही समझते हैं कि अेक हृद तक विषय-सेवामें रहनेके बाद कुछ आराम मिलना चाहिये, मनुष्यको रिटायर्ड होनेका मौका मिलना चाहिये। अिस हालतमें आज समाज-शास्त्रीय चिंतनकी बहुत जरूरत है। अगर हरअेकके जीवनमें ये दो विभाग समुचित भावसे रहें तो आपको कार्यकर्ताओंकी किसी प्रकारकी कमी नहीं रहेगी और अुनका स्तर भी अूंचा रहेगा।

विनोबा

### शिक्षाकी समस्या

लेखक : गांधीजी; अनु० रामनारायण चौधरी

कीमत ३-०-०

डाकखर्च १-२-०

### सच्ची शिक्षा

लेखक : गांधीजी; अनु० रामनारायण चौधरी

कीमत २-८-०

डाकखर्च १-०-०

नवजीवन प्रकाशन भंवर, अहमदाबाद-१४

### समान भाषा और प्रजाभावना

समान भाषाका होना किसी देशके लोगोंमें भाषाचार बढानेका कितना जबरदस्त साधन है, यह हमारे देशमें ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान और सिलोनमें भी आजकल देखनेको मिलता है। यह सच है कि भाषाके सरल कारणके साथ आर्थिक या राजनीतिक संकुचित स्वार्थ जुड़ जाते हैं, परन्तु अुस वजहसे प्रजा-भावना निर्माण करनेकी समान भाषामें जो शक्ति रहती है अुसे दोष नहीं दिया जा सकता। कुशल राजनीतिज्ञोंको समान भाषाकी अिस शक्तिके साथ जुड़े अुसे अनर्थको दूर करके भाषाके निर्दोष आधार पर जनताका संगठन करना चाहिये।

पाकिस्तानमें अुर्दू और बंगालीके बीच झगड़ा चल रहा है। पश्चिम पाकिस्तानका अैसा मत है कि केवल अुर्दू ही राजभाषा रखी जाय। पूर्व पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तानसे बड़ा है; वहां केवल बंगाली भाषा है। अिसलिये वहांके नेता श्री फजलुल हकने हालमें कहा है कि अुर्दूके साथ बंगालीको भी राजभाषा रखा जाय, वरना पाकिस्तानका संविधान खतरेमें पड़ जायगा।

यही हाल आज सिलोनमें है। वहांकी बहुत बड़ी आबादीकी भाषा सिंहली है। परन्तु वहांकी लगभग १० लाख जनता तामिल-भाषी है। अिसलिये यह सोचा जा रहा है कि सिंहलीके साथ तामिल भी राजभाषा रहे। परन्तु अेक पक्ष अैसा खड़ा हुआ है जो सिंहलीको ही राजभाषा बनाना चाहता है। अिस कारण तामिल-भाषी वर्ग कहता है कि अैसा होगा तो हमें 'तामिलनाडू'का अलग प्रदेश बनाना पड़ेगा। मतलब यह कि सिलोनका संविधान खतरेमें पड़ जायगा।

सौभाग्यकी बात है कि भारतकी राजभाषा हिन्दीके सम्बन्धमें हमारे यहां अेकमत है। परन्तु प्रदेश-भाषाओं और हिन्दीके स्थान और अुपयोगके सम्बन्धमें मतभेद है, और भाषावार राज्य-रचनाके विषयमें जोरोसे खींचातानी चल रही है। भाषाके सवालके साथ जुड़कर पैदा होनेवाले 'अतिरिक्त' अंग अिसमें संतापके कारण बन रहे हैं। अैसे अवाञ्छनीय अंगोंको दूर करके समान भाषाके सम्बन्धवाला अेक निर्दोष संगठन-केन्द्र बनानेमें हमारा देश सफल हो जाय, तो कहा जायगा कि अुसने अपनी प्रगतिकी अेक बड़ी मंजिल तय कर ली।

अिस विषयमें बम्बयी तथा पंजाबमें तीव्र भावना फैली हुयी है। बम्बयी राज्यमें प्रश्न बम्बयी शहरका है। अिसका कारण है बम्बयीकी आर्थिक खुशहाली और अुसकी अर्वाचीन शानशौकत। सारे भारतवर्षके पुरुषार्थसे बनी हुयी और अंग्रेजी राज्यकी विरासत यह नगरी किसी अेकभाषी राज्यकी तो कैसे मानी जा सकती है? सब चाहते हैं कि महाराष्ट्र अिस बातको समझने और अुसकी कदर करने जितना देशाभिमान और समझौतेकी वृत्ति दिखावे।

पंजाबमें कौमवाद और भाषावाद दोनोंके मिलनेसे समस्या खड़ी हुयी है। हिन्दू और सिक्ख अपनेको अलग अलग धर्मकी कौमें मानकर चलते हैं और अुस न्यायसे पंजाबी और हिन्दी भाषायें तथा अुनकी अलग लिपियां (गुरुमुखी और नागरी) अिस झगड़ेको बढानेका काम करती हैं। हिमाचल प्रदेशका स्थान बीचमें अुलझन बना हुआ है। अिस समस्याको हम हल कर लें तो कहा जायगा कि कौमवादके विचारोंमें भी हमने काफी सुधार कर लिया है।

८-११-५५

(गुजरातीसे)

मगनभाई देसाई

## चर्म-अद्योगका विकास

भारतमें ढोरोकी संख्या दुनियाके किसी भी देशसे अधिक है। जिसलिये स्वभावतः यह हमारे देशका एक बड़ा ग्रामोद्योग है। आज भी ८० प्रतिशत चमड़ा कमानेका काम तथा ९० प्रतिशत जूते बनानेका काम हाथसे ही होता है। जिस चमड़ेका उत्पादन अधिकतर कुदरती रूपमें मरनेवाले ढोरोकी संख्या पर आधार रखता है। कतल किये जानेवाले ढोरोकी संख्या हमारे यहां बहुत थोड़ी है। जिसके सिवा, कानून तथा सामाजिक और आर्थिक बन्धनोंके कारण मरे हुअे ढोरोके शव भी ठीक समय पर नहीं मिलते। जिसके फलस्वरूप अच्छा चमड़ा नहीं मिलता, जिससे देशको प्रतिवर्ष लगभग १० करोड़ रुपयेका नुकसान उठाना पड़ता है। फिर, दोषपूर्ण पद्धतियोंके कारण जिस अद्योगमें काम करनेवालोंको भी पूरी कमायी नहीं मिलती। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ी हुयी है।

जिस अद्योगमें भी यंत्रोंका प्रवेश हो गया है। हमारे देशमें २४ यंत्रों द्वारा काम करनेवाले बड़े पैमानेके, ५०० हाथसे काम करनेवाले बड़े पैमानेके और २५० यंत्रों द्वारा काम करनेवाले लेकिन छोटे पैमानेके चमड़ा कमानेके कारखाने हैं। उनमें ३५,६५० आदमियोंको रोजी मिलती है। यही काम गांवोंमें व्यक्तिगत रूपमें चमार करते हैं। उसमें ५४,००० लोगोंको काम मिलनेका अन्दाज लगाया गया है। जिसमें उनके कुटुम्बके लोगोंका समावेश नहीं किया गया है। जिस अद्योगके पूरक अद्योग यानी जूते बनानेके अद्योगमें जिस समय १२ बड़े पैमानेके कारखाने काम कर रहे हैं, और छोटे पैमानेके तो असंख्य कारखाने हैं। १९५४ में ९ करोड़ ४ लाख जूते भारतमें बने थे। जिनमें से ५४ लाख यानी ५.९ प्रतिशत बड़े कारखानोंमें और बाकीके ९४ प्रतिशत छोटे कारखानों और गांवोंमें बने थे। १९५१ की जनगणनाके अनुसार जिस अद्योगमें ४,०१,६७२ कारीगर काम करते हैं।

जिस अद्योगके विकासके लिये नीचेकी बातों पर ध्यान देना जरूरी है :

१. ढोरोके शवकी ठीक समय पर प्राप्ति और उसके सारे अवशेषोंका पूरा उपयोग।
२. तालीम पाये हुअे निरीक्षकोंकी देखरेखमें सुधरी हुयी पद्धतियोंसे चमड़ा कमाना।
३. चुने हुअे केन्द्रोंमें असी तालीमकी व्यवस्था करना, जिससे चमड़ेकी जातमें सुधार हो।
४. जिस अद्योगके कारीगरोंको व्यवस्थित और योजनाबद्ध सहायता।

जिस अद्योगके विकासके लिये यह जरूरी है कि बड़े कारखानोंकी होड़ पर रोक लगायी जाय; जिसके लिये अद्योगके जिन दोनों विभागोंके लिये उत्पादनका समान कार्यक्रम बनाया जाना चाहिये। परन्तु असा कार्यक्रम बनाया जा सके, जिससे पहले यह जान लेना चाहिये कि हमारे देशमें चमड़ेकी और मुससे बननेवाले मालकी कितनी जरूरत आज है और आगे होगी।

१९५४ में देशके भीतर १०८.५ लाख बड़े चमड़ोंकी और ४२.५ लाख छोटे चमड़ोंकी मांग थी; और निर्यात २६ लाख पकाये हुअे तथा ६५ लाख कच्चे चमड़ोंका हुआ था। यह अन्दाज लगाया गया है कि दूसरी पंचवर्षीय योजनाके दौरानमें जूतोंकी खपत, जो आज गांवोंमें प्रति ५ व्यक्तियों पर १ जोड़ और शहरोंमें प्रति २ व्यक्तियों पर १ जोड़ है, बढ़कर गांवमें प्रति ९ व्यक्तियों पर २ जोड़ और शहरमें प्रति ५ व्यक्तियों पर २ जोड़ हो जायगी। अर्थात् जूतोंकी जरूरतमें २० प्रतिशत वृद्धि

होगी। चमड़ेकी जात सुधर जानेसे विदेशोंका निर्यात भी बढ़ेगा। जिस तरह कुल मिलाकर १७६.४ लाख बड़े चमड़ों और १३२.४ लाख छोटे चमड़ोंकी मांग रहेगी। साथ ही साथ, ढोरोकी संख्या भी हर साल २ प्रतिशत बढ़कर ३४१२ लाख हो जायगी। जिसके फलस्वरूप १९६१ में २९० लाख बड़े चमड़े और ४६९ लाख छोटे चमड़े मिल सकेंगे।

जिसलिये अब प्रश्न उत्पादनका सामान्य कार्यक्रम बनानेका रह जाता है। खादी ग्रामोद्योग बोर्डका सुझाव यह कार्यक्रम जिस प्रकार बनानेका है :

१. चमड़ा पकानेवाले यांत्रिक कारखानोंकी १९५४ की उत्पादन शक्तिमें वृद्धि न होने दी जाय।
२. ६० लाख बड़े चमड़े और ७० लाख छोटे चमड़े पकानेका कार्य ग्रामोद्योगोंको सौंपा जाय।
३. ४० लाख छोटे चमड़े बड़े पैमानेके यांत्रिक कारखानोंको सौंपे जाय और १० लाख छोटे चमड़े छोटे पैमानेके यांत्रिक कारखानोंको सौंपे जाय।
४. बाहर भेजे जानेवाले कच्चे छोटे चमड़ोंकी वार्षिक संख्या तय कर दी जाय और अतरोत्तर उनका निर्यात घटाया जाय।
५. जंगलोसे प्राप्त होनेवाले चमड़ा कमानेके साधनोंकी रक्षा की जाय और मद्रास और उत्तर प्रदेशमें खास तौर पर अन्हें बोया जाय।

६. ढोरोके चमड़ेको नुकसान पहुंचानेवाली दाग लगानेकी या आर चुभानेकी प्रथाके सम्बन्धमें तथा ढोरोके शव उठानेमें पैदा होनेवाली कठिनाइयां दूर करनेके सम्बन्धमें कानून बनाये जाय।

६. जूतोंका सारा अतिरिक्त उत्पादन ग्रामोद्योगके लिये सुरक्षित कर दिया जाय।

८. गांवोंके कारीगरोंको कच्चा माल प्राप्त करने और अपना माल बेचनेमें मदद की जाय।

जिस अद्योगके विकासके लिये बोर्डने दूसरी पंचवर्षीय योजनामें ३,००० शव प्राप्त करनेके केन्द्र, ३०० गांवोंमें चमड़ा कमानेके केन्द्र और ७५ गांव बनानेके केन्द्र खोलने तथा ३०,००० मोची तैयार करनेकी सूचना की है। साथ ही ४ शव-प्राप्तिके तालीम केन्द्र, २० चमड़ा कमानेके तालीम केन्द्र, ८० घूमनेवाले मंडल और ५० बिक्री-केन्द्र खोलनेकी भी सूचना की है।

अपूरके तंत्रकी रचना करनेमें कुल ३१४.१ लाख रुपये खर्च होंगे। जिसके सिवा, जिस अद्योगको प्रोत्साहन देनेके लिये कर्ज और राहतके रूपमें १५४.९५ लाख रुपये देने तथा सारे केन्द्रोंको चालू पूंजीके लिये १५४.८५ लाख रुपये देनेकी बोर्डने सूचना की है।

जिस सारी योजनाका कुल खर्च ५.४ करोड़ रुपये होगा, जब कि दूसरी ओर जिसके फलस्वरूप ३८,२५० अधिक आदमियोंको रोजी मिलेगी और ६४२.८ लाख रुपयेका माल उत्पान्न होगा।

यह पशु-पालनके साथ जुड़ा हुआ बुनियादी अद्योग है, जिसलिये अपूर बतायी दृष्टिसे जिसका विकास करना जरूरी है। जिससे दो लाभ होंगे : (१) राष्ट्रीय धनकी बरबादी नहीं होगी और (२) नया धन पैदा होगा तथा लोगोंको घर बैठे रोजी मिलेगी।

(गुजरातीसे)

वि०

## हमारे गांवोंका पुनर्निर्माण

लेखक : गांधीजी

संपादक : भारतन् कुमारप्पा

कीमत १-८-०

डाकखर्च ०-५-०

नवजीवन प्रकाशन मन्वर, अहमदाबाद-१४

## हरिजनसेवक

२६ नवम्बर

१९५५

### राजभाषा कमीशन

अब तक पाठकों ने राजभाषा कमीशन के अध्यक्ष श्री बी० जी० खेरका अत्यन्त विचारप्रेरक भाषण \* देखा और पढ़ लिया होगा। मुझे लगता है कि पाठकों को राजभाषा कमीशन का परिचय कराने में मैंने देर कर दी। वह काम मैं अब कर रहा हूँ।

राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान की धारा ३४४ के अनुसार जिस कमीशन को नियुक्त की थी, जो संविधान के आरंभ से पांच वर्ष बाद राष्ट्रपति के लिये ऐसा करना जरूरी ठहराती है। उस धारामें बताया गया है कि जिस कमीशनमें एक अध्यक्ष और संविधान की आठवीं सूचीमें गिनायी गयी भारत की विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करनेवाले दूसरे सदस्य होंगे, जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। जिस तरह जिस कमीशनमें संविधानमें अलिखित भारत की १४ भाषाओंमें से हर एक के प्रतिनिधि हैं।

कमीशन को जिन विषयों की जांच करनी है, वे नीचे दिये जाते हैं :

“१. कमीशन का यह कर्तव्य होगा कि वह नीचे लिखी बातों के बारेमें राष्ट्रपति से सिफारिश करे—

(अ) संघ के सरकारी हेतुओं के लिये हिन्दी भाषा का उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ उपयोग;

(ब) संघ के सरकारी हेतुओंमें से सब या किसी एक के लिये अंग्रेजी भाषा के उपयोग पर प्रतिबन्ध;

(स) धारा ३४८ में बताये गये हेतुओंमें से सब या किसी एक के लिये उपयोगमें ली जानेवाली भाषा +;

(द) संघ के खास तौर पर बताये हुये हेतुओंमें से एक या अधिक के लिये उपयोग किये जानेवाले अर्कों का रूप;

(घ) समय की ऐसी सूची तैयार करना तथा ऐसा तरीका बताना जिसके मुताबिक हिन्दी धीरे धीरे संघ की राजभाषा के नाते तथा संघ और राज्य-सरकारों और एक राज्य-सरकार व दूसरी राज्य-सरकार के बीच के व्यवहार की भाषा के नाते अंग्रेजी का स्थान ले सके।

“२. अपनी सिफारिशें करनेमें कमीशन भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक प्रगतिका तथा सरकारी नौकरियों के सम्बन्धमें अ-हिन्दीभाषी प्रदेशों के लोगों के न्यायपूर्ण दावों और हितों का अचित्त ध्यान रखेगा।”

कमीशन तुरन्त उसे सौंपे हुये काममें लग गया। उसने एक व्यापक प्रश्नावली प्रकाशित की, और अब वह देश का दौरा करके उन मुद्दों पर लोगों की साक्षी अिकट्ठी कर रहा है जिन पर उसे अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। ये मुद्दे सामान्यतः अपर बताये गये जांच के विषयोंमें आ गये हैं।

पाठक देखेंगे कि संविधान के मातहत कमीशन को जो मुख्य कार्य सौंपा गया है वह जिस बात का निश्चय करने का है कि

\* देखिये ‘हरिजनसेवक’ के ता० २९-१०-५५ और ता० ५-११-५५ के अंक।

+ धारा ३४८ में बताये गये हेतु जिस प्रकार हैं :

(१) सुप्रीम कोर्ट की और प्रत्येक हाईकोर्ट की कार्रवायी, (२) पार्लमेन्ट और सारी राज्य-धारासभाओं के बिल और अक्ट, (३) संविधान के मातहत या पार्लमेन्ट अथवा किसी राज्य की धारासभा द्वारा बनाये गये कानून के मातहत निकाली जानेवाली सारी आज्ञायें, नियम, नियंत्रण और उप-कानून।

संघ के सरकारी हेतुओं के लिये हिन्दी का बढ़ता हुआ उपयोग कैसे किया जा सकता है, और इसके लिये एक समय-सूची तैयार करने का है। ये दोनों बातें अपर बताये गये जांच के विषयों से सम्बन्धित पैरा-१(घ) में स्पष्ट रूप से कही गयी हैं। स्कूलों और कॉलेजों में हिन्दी के उपयोग और शिक्षण के बारेमें कोअी निर्णय करना राजभाषा कमीशन का सीधा कार्य नहीं है, जैसा कि कुछ लोग मानते मालूम होते हैं। यह एक ऐसा प्रश्न है, जिसकी छानबीन पहले दो कमीशन—अच्छ शिक्षा के लिये राधाकृष्णन् कमीशन और माध्यमिक शिक्षा के लिये मुदालियर कमीशन—कर चुके हैं और सरकार के सामने उन की रिपोर्टें भी पेश हो चुकी हैं। लेकिन अपर का पैरा-२ परोक्ष रूपमें यह कहता है कि कमीशन जांच-सम्बन्धी विषयों के पैरा-१में बताये गये मुद्दों के बारेमें अपनी सिफारिशें पेश करते समय भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक प्रगतिका तथा सरकारी नौकरियों के सम्बन्धमें अ-हिन्दीभाषी लोगों के न्यायपूर्ण दावों और हितों का अचित्त ध्यान रखेगा। जिससे कुछ शिक्षा-सम्बन्धी और शासन-सम्बन्धी मुद्दों की गौण जांच करना कमीशन के लिये जरूरी हो सकता है; राजभाषा कमीशन द्वारा प्रकाशित प्रश्नावली जिन मुद्दों को काफी हद तक छूती है।

कमीशन के अध्यक्ष ने पूना के अपने भाषणमें ठीक ही कहा है कि “जिस पेचीदा प्रश्न पर ब्यौरेवार विचार करते समय पैदा होनेवाले अनेक मुद्दोंमें से किसी भी मुद्दे पर कोअी विचार प्रकट करना मेरे लिये अनुचित और असामयिक होगा, और जिस विषय पर आज की अवस्थामें कमीशन को और उसके अध्यक्ष के नाते मुझे बिलकुल खुला दिमाग रखना चाहिये।” यह नियम उस कमीशन के एक सदस्य के नाते मुझे भी लागू होता है। अनेक कारणोंमें एक कारण यह भी था जिसने अभी तक जिस बारेमें कुछ लिखने से मुझे रोक रखा था।

जैसा कि मैंने शुरूमें कहा है, यह लेख मैं राजभाषा कमीशन के अध्यक्ष ने पूनामें जो महत्त्वपूर्ण बातें अपने भाषणमें कहीं उन की नोंध लेने के लिये और प्रसंगवश पाठकों को कमीशन का परिचय कराने के लिये ही लिख रहा हूँ। यह कहने की तो जरूरत नहीं है कि भारत की लोकतांत्रिक और सांस्कृतिक प्रगति और विकास की दृष्टि से जिस कमीशन का बहुत बड़ा महत्त्व है। राज्य-पुनर्रचना कमीशन ने हालमें ऐसा ही महत्त्व रखनेवाले एक प्रश्न—संघ के राज्यों की पुनर्रचना के प्रश्न—पर अपनी रिपोर्ट राष्ट्र के सामने प्रस्तुत की है। और यह पुनर्रचना मोटे तौर पर संविधानमें गिनायी गयी १४ भारतीय भाषाओं के आधार पर ही होगी। अब राजभाषा कमीशन को यह भी तय करना होगा कि संघ की राजभाषा हिन्दी को नूतन भारतमें, जिसका निर्माण हो रहा है, “संघ और राज्य-सरकारों तथा एक राज्य-सरकार और दूसरी राज्य-सरकार के बीच के व्यवहार” की अखिल भारतीय भाषा के रूपमें कैसे काम करना चाहिये। यह स्पष्ट है कि जिस तरह काम करते हुये हिन्दी एक राष्ट्र के नाते हमारी एकता का निर्माण करनेवाला एक जीवित माध्यम बन जायगी।

श्री खेर ने अपने पूना के भाषणमें कुछ बुनियादी सिद्धान्त पेश किये हैं, जिनके आधार पर जिस प्रक्रिया का विकास होना चाहिये। पहला सिद्धान्त, जैसा कि अन्होंने कहा, है “हमारे समाजमें आज अंग्रेजी भाषाने जो स्थान प्राप्त कर लिया है, उस स्थानसे उसे हटाने का।” जैसा कि अन्होंने बताया, बेशक जिसका यह अर्थ नहीं कि हम उस महान् भाषा का अध्ययन न करें। इसके विपरीत, हमें “अंग्रेजी भाषा पर और/या दूसरी किसी अनुकूल विदेशी भाषा अथवा भाषाओं पर काफी अधिकार रखना चाहिये, ताकि वे भारतीय भाषाओंमें अभी तक अप्राप्य ज्ञानभण्डार की ‘कुंजी’ का और दुनियासँ निरन्तर हो रही शिल्पविज्ञान और

वैज्ञानिक ज्ञानकी तेज प्रगतिके लिये 'खिड़की' का काम वे सकें।" सारा मुद्दा, जैसा कि अन्होंने बहुत संक्षेपमें अपने भाषणमें रखा था, यह है कि "बालिंग मताधिकार, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षण, सामाजिक न्याय और समान अवसरोंकी वृद्धि आदिके जरिये हम अुचित समयमें जो देशव्यापी राष्ट्रीय अुत्थान और नवनिर्माण करनेके लिये वचनबद्ध हैं, अुसे मेरी रायमें भारतीय भाषाओंके सिवा अन्य किसी भाषाके द्वारा करनेकी कल्पना नहीं की जा सकती। बेशक, संविधानकी धाराओंने यह प्रश्न हल कर ही दिया है, अिसलिये यहां अुस पर फिरसे कुछ कहनेकी जरूरत नहीं है।" अथवा जैसा कि श्री खेरने स्पष्ट रूपमें कहा, "भाषाके सम्बन्धमें राष्ट्रीय स्वाभिमानके विचारोंका बेशक महत्त्व है, क्योंकि वह किसी प्रजाके सम्पूर्ण राष्ट्रीय जीवनको बहुत गहराअीसे छूती है।"

अिसलिये श्री खेरने यह चेतावनी भी दी है कि "भाषा-सम्बन्धी जो अटपटी और ब्यौरेवार क्रांति हमें करनी है, अुसमें" यह याद रखना चाहिये कि "कोअी जीवित भाषा रोजकी बोलचालकी भाषामें, सामान्य व्यावहारिक दुनियामें और बाजारमें जिन्दा रहती है, न कि शब्दकोश रचनेवालोंके शब्दकोशोंमें।... साधारण मनुष्यको भाषाकी शुद्धिके सिद्धान्तोंमें कोअी दिलचस्पी नहीं होती, और शायद अुसकी यह वृत्ति ठीक है।"

अेक दूसरा महत्त्वका मुद्दा, जो श्री खेर हमारे ध्यानमें लाये, यह है कि "संविधानने भारतकी सारी भाषाओं और लिपियोंको काफ़ी संरक्षण और गारंटियां देनेकी भी व्यवस्था की है।" अिसलिये संघके सरकारी हेतुओंके लिये हिन्दी भाषाके बढ़नेवाले अुपयोगको दृष्टिमें रखते अुसे हमारी भाषाकी समस्या "व्यावहारिक नीतिकी समस्या है, जिस पर धार्मिक या पुनरुत्थानवादकी दृष्टिसे भिन्न धर्मनिरपेक्ष दृष्टिसे, प्रान्तीय या साम्प्रदायिकसे भिन्न राष्ट्रीय दृष्टिसे और सैद्धान्तिकसे भिन्न व्यावहारिक दृष्टिसे विचार किया जाना चाहिये।"

ये कुछ मुख्य मुद्दे हैं, जो श्री खेरने देशके सामने रखे हैं। हम कह सकते हैं कि भावी भारतके भाषावार स्वरूपका, जिसकी व्याख्या खुद संविधानने सामान्य शब्दोंमें हमारे लिये कर दी है, प्राफ़ खींचनेके लिये ये मुख्य अक्ष हैं।

१२-११-५५  
(अंग्रेजीसे)

मगनभाई देसाई

### जीवन और संहारका स्तर

१५ सितम्बर, १९५५ का 'पीस न्यूज' नीचेकी खबर देता है:

"डॉस अेन्डरे डच्यूशलैण्ड' नामक अेक जर्मन अखबार युद्धमें अेक दुश्मन सैनिकको मारनेके लिये अुसे खर्चके अंदाजी आंकड़े, जो अमेरिकन डॉक्टरोंके परिषद्के सामने पेश किये गये थे, अिस प्रकार देता है:

जूलियस सीज़रने खर्च किये	पाँ०	शि०	पेंस
नेपोलियनने खर्च किये	-	३	४
अमेरिकाकी आजादीके लिये लड़ गये युद्धमें हुआ खर्च	१०००	-	-
पहले विश्वयुद्धमें मित्रराष्ट्रों द्वारा किया गया खर्च	१६६६	-	-
दूसरे विश्वयुद्धमें अकेले अमेरिका द्वारा प्रत्येक मृत जर्मन या जापानी सैनिकके लिये किया गया खर्च	७५००	-	-
	७५०००	-	-

अिस प्रकार जीवनके स्तरके साथ पश्चिमके देशोंमें संहारका खर्च भी बढ़ता रहा है! आज भीतर ही भीतर लड़ रही पश्चिमी दुनियाकी नयी अर्थरचनाके निर्माणमें अिन दोनों बातोंने मिलकर तो हाथ नहीं बंटया हो?

३-११-५५  
(अंग्रेजीसे)

म० प्र०

### लोकशाही और निष्णातशाही

बम्बअीकी निचली विधानसभामें बल्लभ विद्यापीठके बिलकी चर्चा हो रही थी, अुस समय—अैसा मालूम होता है कि वाद-विवादकी गर्मीमें—मुख्यमंत्रीने कहा कि निष्णात लोग कोअी देवता नहीं हैं कि वे जो कहें अुसे वेद-वाक्य मान लिया जाय। और फिर व्यंगपूर्वक प्रश्न किया कि निष्णात लोगोंको कभी अेकमत होते अुसे देखा है? अखबारवालोंने अुनकी अिस अुक्तिको जरा ज्यादा अुठा लिया, अन्यथा वात विनोदमें लेने-जैसी ही थी।

जहां तक हम सर्वज्ञ नहीं अुसे, वहां तक दूसरेकी बात सुनना तो पड़ेगी ही। और निष्णातों पर तो हम सभी हर कदम पर जाने-अनजाने आवार रखते हैं। लेकिन अुसका अर्थ यह हरगिज नहीं है कि हम अपनी सामान्य विवेकशक्ति दूसरोंको सौंप दें। किसी भी अेकांतिक 'शाही' की तरह निष्णातशाही भी अनिष्ट है।

लेकिन हमारा ही विवेक सही है, अैसा भी नहीं माना जा सकता यद्यपि विवेक-शक्तिका अुपयोग करना चाहिये, यह मनुष्यके बुद्धि-व्यापारका कानून है; हां, यह अुपयोग नम्रतापूर्वक होना चाहिये।

लेकिन मुख्यमंत्रीके अिस विधानके विषयमें बी० सी० जी० वाले क्या कहते हैं? वे क्या मानकर चलते हैं? वे तो निष्णातोंकी ही बातको मानकर चलते हैं, अैसा मालूम होता है। निष्णात लोग शायद ही कभी अेकमत होते हैं, यह बात यहां तो और भी सच है। कुछ डॉक्टर कहते हैं कि बी० सी० जी० अच्छी चीज है, तो अितने ही कुशल डॉक्टर अिसकी अुलटी बात कहते हैं। सरकारें अिनमें से पहले पक्षके निष्णातोंको देवता मानकर ही तो चल रही हैं! वे अुन्हें सचमुच देवता मानती हैं, क्योंकि निष्णात लोग तो अैसा दावा करते हैं कि हम, दवाके द्वारा क्षयसे मुक्ति देकर गोया देवताका वरदान ही देते हैं। अुदाहरणके लिये, केन्द्रीय सरकारकी आरोग्य-मंत्री राजकुमारी श्री अमृतकुंवर कहती हैं कि डॉ० राय और डॉ० जीवराज जैसे डॉक्टर बी० सी० जी० की लसीको अच्छा कहते हैं। अिसलिये अब देशके बच्चोंकी खैर नहीं है; वे अिस लसीके झपाटेसे बच नहीं सकते!

लेकिन राजाजी यहां अलग पड़ते हैं। वे कहते हैं कि निष्णात लोग तो बी० सी० जी० के खिलाफ भी कहते हैं। अिसलिये हमें निष्णात लोगोंसे आतंकित नहीं होना चाहिये। हमें अिस लसीके बारेमें स्वतंत्र विचार करना चाहिये। निष्णात डॉक्टर लोग तो हमेशा अिन्हीं बातोंमें व्यस्त रहते हैं, अिसलिये अुनके विचार ज्यादा रंगे अुसे होते हैं। अिसके सिवा डॉक्टरोंके निष्णातोंमें भी तो दो मत हैं!

अिन निष्णात लोगोंका कोअी अलग तर्कशास्त्र होता है, अैसा मालूम होता है। युद्धकालमें जब लोगोंको 'मिलो' खिलानेकी आवश्यकता पड़ गयी थी, अुस समय वे अुसके अनुकूल तर्क—और वह भी शास्त्र-शुद्ध परिभाषामें—प्रकाशित करते थे। जब गेहूं कम मिलते और बाजरी ज्यादा मिलती थी, अुस समय बाजरीके आहार-सम्बन्धी गुण-दोषके बारेमें समझाकर लोगोंको अुसके अनुकूल बनानेका प्रयत्न करते थे। और ज्यादा ताजा अुदाहरण चाहिये तो वनस्पतिका मौजूद है!

'जिसका खाओ धान, अुसका गाओ गान' अिस अर्थकी अेक अंग्रेजी कहावत है। विज्ञानमें भी अब अेक 'गवर्नमेंट सन्सिडाअिज्ड (यानी सरकारी पैसेके बल पर चलनेवाला) विज्ञान' चल पड़ा है। वैज्ञानिक अनुसंधानका खर्च आज अितना ज्यादा होता है कि वैज्ञानिकोंको अुसके लिये सरकारकी शरण लेना पड़ती है। और दुनिया भरमें सरकारें किस तरह चलती हैं, यह तो सब

जानते हैं। वे मतभेद या विरोध झट सहन नहीं करतीं, विरोध अन्हें अच्छा नहीं लगता। उसके नौकरोंको तो जिस सम्बन्धमें अन्तमें चुप्पी स्वीकार करके शिस्तका पालन करना ही पड़ता है। और यह जाहिर है कि जो उसके अनुकूल होते हैं अन्हें सरकार अपने कामकी हद तक प्रमाणभूत निष्णात मानती है।

यह सब होते हुअे भी सार्वजनिक कामोंके लिये निष्णातोंके झगड़ोंमें से रास्ता तो निकालना ही चाहिये। और यह रास्ता सच्चा हो जिसकी सावधानी भी रखनी चाहिये। यह किस तरह होता है उससे ही जिस बातकी परीक्षा होती है कि देशका कारोबार किस 'शाही' से चल रहा है। उसीसे यह प्रगट होता है कि लोकशाही चल रही है या निष्णातशाही, या तानाशाही। लोकशाही निष्णातशाही नहीं है, लेकिन वह निष्णातोंका अिनकार नहीं करती। वह अुनकी मदद लेती है, लेकिन अुनके पीछे-पीछे नहीं चलती। इसी कारण हम देखते हैं कि अधिकांश राज्योंमें निर्माण-विभागमें अिन्जीनियर या आरोग्य-विभागमें डॉक्टर-वैद्य मंत्री नहीं होते। यद्यपि बी० सी० जी० के बारेमें तो वे अपने अनुकूल निष्णातोंको देवता मानकर चलते हैं, और दूसरे विचारको रोकते, दबाते हैं या नगण्य समझते हैं। इसी बातकी राजाजी टीका करते हैं।

### निष्णात और शासनाधिकारी

मुझे लगता है कि निष्णातों और शासनाधिकारियोंमें गजग्राह जैसी खींचतान लोकशाहीका एक सामान्य भयस्थान है। क्या ऐसा नहीं है? निष्णात तो निष्णात ही है। किसी एक विषयके बारेमें वह अितना अधिक जानता है कि उसके दिमागमें किसी भिन्न विचार या अनुमानके लिये जगह ही नहीं होती। शासनाधिकारीकी बात जिससे अुलटी होती है। उसे अनेक बाजुओंकी फूटकर, रंग-बिरंगी या मिर्च-मसालेवाली अपार जानकारी होती है। परन्तु उसकी दृष्टि मुख्यतः जिस बात पर केन्द्रित रहती है कि उसकी व्यवस्था ठीक चलनी चाहिये। लेकिन व्यवस्थाका भ्रष्टार्थ भी हो जाता है; अधिकारी ऐसा समझने लगते हैं कि व्यवस्था यानी जो बात या विचार अुन्हें मंजूर हो वह, यानी अुनकी अपनी सत्ता। इसीलिये तो भारतके विगत राज्यकालमें शासनका स्वरूप नौकरशाहीका हो गया था।

राज्य-व्यवस्थाका काम भी एक निष्णातों द्वारा किया जाने-वाला कार्य ही है, और उस अर्थमें शासनाधिकारियोंकी गिनती भी निष्णातोंमें की जा सकती है। लोकशाही इसके भी परेकी चीज है।

श्री जयकरने, कभी वर्ष हुअे, जिस विषयकी चर्चा करते हुअे एक अुदाहरण दिया था। अुन्होंने कहा था कि कल्पना करो कि हमें कोअी अिन्जीनियरिंगसे सम्बन्धित काम करना है। अिन्जीनियर लोग कहेंगे कि ऐसा करो, वैसा करो। वे तो पहले अपनी विद्याका प्रदर्शन करनेकी बात सोचेंगे और कामकी जरूरतको गौण स्थान देकर उसके अन्दर बिठानेकी कोशिश करेंगे। होना ऐसा चाहिये कि कामकी जरूरत शासनाधिकारी बताये और उसके अनुसार अिन्जीनियर अपनी विद्या बतलाये। अब इसके बदले अगर अिन्जीनियर अपनी विद्याके अनुसार कामकी योजना करनेको कहे और शासनाधिकारी उसके कहे अनुसार चले तो? जिसे निष्णातशाही कहना पड़ेगा। शासनाधिकारीकी दृष्टि उससे आगे जाती है। अिन्जीनियरकी विशेषज्ञता जिसमें है कि बताया हुआ काम किस तरह किया जाय, जिसमें नहीं कि कौन-सा काम किया जाय। किन्तु कभी बार निष्णात लोग जिस बारीक मर्यादाको लांघ जाते हैं और व्यवस्थापक उसमें फंस जाते हैं। इसीलिये

कहा जाता है कि राज्य-व्यवस्थापक केवल व्यवस्थापक ही न हों, अुन्हें अुदारनीतिज्ञ राजपुरुष होना चाहिये और अपने अहं पर नियंत्रण रखना आना चाहिये।

२६-९-'५५  
(गुजरातीसे)

मगनभाई देसाई

## विविध विचार

### वर्षगांठ मनाना

मेरे खयालमें वर्षगांठ मनानेका रिवाज दुनियाकी सारी प्रजाओंमें होगा। कोअी समाज-विज्ञान-शास्त्री खोज करके बतावे तो जिस सम्बन्धकी जानने लायक बातें सामने आयेंगी।

जन्मदिन मनानेमें एक विशेष आनन्दका भाव होता है। अेकाघ सन्त, भक्त या दार्शनिकके सिवाय दुनियाके सभी लोग जिसमें आनन्द अनुभव करते होंगे। जिसका कारण स्पष्ट है। मूलमें देखा जाय तो वर्षगांठ सदा सर्वदा आनन्दमय अनन्त जीवनका अुत्सव है; सदा बहनेवाले जीवनकी अमृतताकी प्रतीकरूप वर्षगांठके द्वारा हम उस परम प्रभुको अपना अर्घ्य अर्पण करते हैं। परन्तु आनन्दके जिस मूल कारणको जाने बिना सब लोग सामान्यतः व्यवहार करते हैं और जन्मदिवसका आनन्द मनाते हैं।

भिन्न भिन्न प्रजायें जन्मदिन जिस तरह मनाती हैं, उसकी विधि या रीति ध्यान देने जैसी होती है। अुदाहरणके लिये, युरोपमें लोग अमुक वजन और आकारकी 'केक' बनाते हैं, उसे काटते हैं और सबको उसका टुकड़ा टुकड़ा बांटते हैं। मानो वे अपने शरीरका एक भाग देकर सबके साथ अपनी अेकता और प्रेम प्रकट करते हैं। आयुकी संख्याके अनुसार दीये जलाते हैं और अुन्हें बुझानेकी विधि पूरी करते हैं। इसके पीछे कहीं यह भावना तो नहीं हो कि अन्तमें जीवन-दीप बुझने ही वाला है!

'हरिजन' के एक पाठकने अुत्तरभारतसे पत्र लिखकर पूछा है कि हम जो वर्षगांठ मनाते हैं, उसमें क्या जिस बातका भी आनन्द नहीं मनाते कि 'मरण-गांठ' एक वर्ष और नजदीक आयी है? बात सच है। लेकिन दुनियाके साधारण लोग जिस तरफ नहीं देखते।

हमारे देशमें वर्षगांठ मनानेका कोअी व्यापक संस्कार नहीं है। पश्चिमके लोगोंकी देखादेखी शायद यह बढ़ने लगा है, और सुखी व खुशहाल लोग ही उसे मनाते हैं। परन्तु यह बहुत व्यापक रिवाज तो नहीं कहा जा सकता।

फिर भी क्या ऐसा नहीं लगता कि सार्वजनिक जीवनके क्षेत्रमें आजकल यह बात कुछ बढ़ने लगी है? यह युग विज्ञापन-बाजीका है; किसी न किसी तरह अधिकसे अधिक प्रसंगोंका आयोजन करके समारोह करनेकी वृत्ति बढ़ती जा रही है। वर्षगांठ 'वनप्रवेश', षष्ठिपूर्ति, जयंती, यूह दिवस-वह दिवस, अमुक व्यक्तिके लिये अभिनन्दन-सभा वगैरा तरीके मशहूर हो गये हैं। पुस्तक प्रकाशनकी विधि भी होने लगी है। अिन सबके पीछे सार्वजनिक जीवनमें अैसे मौके देखनेकी भूख—और कुछ लोगोंके लिये तो चटपटी भी कहा जा सकता है—काम करती होती है। अैसे प्रसंगोंका आयोजन किसके लिये किया जाता है, यह भी सूचक होता है। अखबारवाले अुनके चित्रों सहित समाचार देकर अिन भावोंको प्रोत्साहन देते हैं। और अिन सबमें एक खास सामाजिक विवेक और अभिरुचिसे आगे बढ़कर खुशामद और दंभ वगैराकी भी गंध आने लगती है, अैसा अिशारा अुप-रोक्त पत्रकारने किया है।

अिन सबमें आगे चलकर अैसा भी होने लगता है कि बड़े आदमियोंको अपनी स्तुति सुनना पसंद आता है और अुनकी

स्तुति करनेवाले जब अुनके मानमें समारोह करनेके मौकेकी ताकमें रहते हैं तो बड़े आदमी जैसे मौके तुरन्त हूँककर दे भी देते हैं। इस तरह परस्पर भावसे यह सब चलता है! समाजके स्वास्थ्यके लिये जिन समारोहोंमें भी अमुक हद तक सुरुचि, विवेक-मर्यादा वगैराका आना आवश्यक है। वर्ना सार्वजनिक जीवनके वातावरणमें दंभ, खुशामद वगैराकी गंध बहुत ज्यादा बढ़ जानेसे दम घुटनेकी नौबत आ सकती है। स्व० रमणभाभी नीलकण्ठने वर्षों पूर्व 'मानपत्रके पाठ' द्वारा जिस विषयमें जो व्यंग किया था, वह क्या सार्वजनिक जीवनमें सदा जीवित रहनेवाली वस्तु नहीं है?

२५-९-'५५

म० प्र०

### विद्यार्थी-मंडलोंकी परेशानी

अखिल गुजरात विद्यार्थी कांग्रेसकी बैठक ता० २४-९-'५५ को खेरवा (जिला महेसाणा) में हुई। अुसमें मंगल-प्रवचन करनेके लिये मुझे बुलाया गया था। अुस संबंधमें विद्यार्थी कांग्रेसके मंत्रीने अपने पत्रमें जो कुछ लिखा था, वह शिक्षा-जगत्के सामने रखने जैसा है। अुन्होंने लिखा था :

“मेरी और विद्यार्थी-प्रवृत्तिकी जो परेशानी है, अुसके निवारणके लिये आप अुद्घाटनके मौके पर कुछ मार्गदर्शन कर सकें, इस हेतुसे नीचेकी बातें केवल सूचनाके रूपमें नम्रभावसे आपके सामने रखता हूँ :

“१. पहले शिक्षण-संस्थायें केवल सरकारी नीकर तैयार करनेके कारखानों जैसी थीं। इसलिये अुनमें राष्ट्रीयता और पूर्ण व्यक्तित्वके विकासके अवसरका जो अभाव रहता था, अुसकी पूर्ति गांवों और शहरोंके विद्यार्थी-मंडल करते थे।

“आज परिस्थिति बदल गयी है। पहले जो प्रवृत्तियां विद्यार्थी-मंडल करते थे, अुन्हें शालाओं, कॉलेजों और सरकारने स्वीकार कर लिया है। अैसी स्थितिमें अब हमारे जैसे स्वतंत्र विद्यार्थी-मंडल क्या करें? वे कौनसी प्रवृत्ति चलायें?

“२. दूसरे, आज विद्यार्थियोंमें 'अिनीशियेटिव' (पहल करनेकी वृत्ति) का विकास हो, इस तरह कोअी काम होता नहीं दीखता। हर जगह अुपरसे आदेश आते हैं, जो आम तौर पर विद्यार्थियोंको पसन्द नहीं आते। क्या अैसा कुछ नहीं हो सकता, जिससे १९४२ के अरसेमें विद्यार्थी स्वयंस्फूर्तिसे जैसे प्रवृत्तियां चलाते थे, वैसे आज भी चला सकें? विद्यार्थियोंके जोश और अुत्साहका किस तरह अुपयोग किया जाय कि अुनमें 'अिनीशियेटिव' का गुण बढ़े?

“३. शालाओंमें बाहरी परिवर्तन हुअे हैं। लेकिन अभी तक शिक्षण-संस्थायें चलानेवाले बहुतसे लोग पुराने विचारोंकी पकड़से छूट नहीं सके हैं, जब कि विद्यार्थी समाजमें जो परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं, अुसके परिणामस्वरूप वे स्वभावतः कुछ नया करनेकी अभिलाषा रखते हैं। पुराने विचारोंके शिक्षक और शिक्षाशास्त्री अुनकी आकांक्षायें पूरी नहीं कर सकते। इसके कारण विद्यार्थियोंमें अेक ओर व्यग्रता और क्रोधकी भावना तथा दूसरी ओर निराशा और मिथ्याभिमानकी भावना दृढ़ होती पायी जाती है, जो सचमुच बड़े महत्त्वका प्रश्न है।

“४. यही कारण है कि छोटी छोटी बातोंसे अुत्तेजित होकर वे हड़तालें या दंगोंका आसरा लेते हैं। अतः प्रश्न यह है कि अुनकी कठिनाअियों, असुविधाओं, अन्यायों और शिकायतोंके निवारणके लिये अुन्हें कोअी शान्तिपूर्ण पद्धति नहीं बतायी जा सकती? क्या इसकी कोअी 'टेकनीक' नहीं हो सकती? क्या शिक्षा-विभाग इस संबंधमें कुछ नहीं कर सकता?”

में अपना भाषण लिखकर नहीं ले जा सका था। अुस अवसर पर मैंने जो बातें कही थीं, अुनमें जिन प्रश्नोंका भी जिक्र किया था। यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि अिनके अुत्तरोंकी गहराअीसे मैंने चर्चा की थी, फिर भी अुन्हें छूते हुअे कुछ बातें कही थीं। अुनमें से कुछ मुद्दों पर आगे स्वतंत्र रूपसे चर्चा करनेका मेरा विचार है। इस समय तो अुपरके प्रश्न पाठकोंकी चर्चके लिये यहां पेश करता हूँ। जाहिर है कि ये प्रश्न विद्यार्थी-प्रवृत्तिके मूलको छूते हैं।

२५-९-'५५

म० प्र०

### राजनीतिके रंग

अगस्त माहमें पटनामें जो दंगे और गोलीबार हुअे, अुससे देशमें काफी हो-हल्ला मचा और चर्चा चली। बिहार सरकार ही नहीं, परंतु जवाहरलालजी और जयप्रकाश नारायणजी भी अुसमें आते हैं। कहा जाता है कि विद्यार्थियोंने राष्ट्रध्वजका किसी तरह अपमान किया। शायद बम्बयीमें भी अैसा हुआ था। लेकिन बात यह है कि न तो पटनामें और न बम्बयीमें दरअसल अैसी ओछी देश-भक्तिवाला कोअी होगा, जो अपने राष्ट्रध्वजका अपमान करनेकी बात कभी सोचेगा। सब कोअी जानते हैं कि गुस्सेमें जब आदमी आ जाता है, तब न करने जैसी बात भी कर बैठता है। अुसमें भी हुल्लड़बाजीमें बह जाने पर तो यह चीज और भी जल्दी और जोरदार ढंगसे हो जाती है, अैसा मानस-शास्त्री कहते हैं।

विचार करने पर अेक बात यह खयालमें आयेगी कि दोनों जगह लोगोंकी भीड़ सरकारसे चिढ़ गयी थी। इससे लोग राष्ट्रध्वजको सरकारका ध्वज मान बैठे। और फिर सरकार पर की चिढ़ राष्ट्रध्वज पर अुतर गयी, अैसा लगता है।

परंतु जवाहरलालजी पटनाकी घटनासे अितने ज्यादा चिढ़ गये कि अुन्होंने कहा, राष्ट्रध्वजकी शान रखनेके लिये मौका आने पर लोगोंकी हत्या भी करना पड़ सकता है! इस पर तरह तरह की टीकायें हुअी हैं। कुछ वर्ष पहले कालाबाजार करनेवालोंको फांसी पर चढ़ा देनेकी बात भी अुन्होंने नहीं कही थी? अब साहित्यिक यदि अैसा सोचें तो ठीक हो कि भावोद्रेक अेक अर्थालंकार है। या अुसकी गिनती अतिशयोक्ति या अत्युक्तिमें की जायगी?

अेक अखबारने लिखा कि राष्ट्रध्वजकी शान बड़ी या अितसान बड़ा? और इसकी दलीलमें अेक जगह रंगमें आकर स्व० किशोर-लालभाभीने राष्ट्रध्वजका जो वेदान्ती पंचीकरण किया है, वह याद आया। अुसमें बहुत करके अुन्होंने यह कहा है कि राष्ट्रध्वज अन्तमें तो वस्त्रका अेक टुकड़ा ही है न! बात सच है; परंतु टुकड़े टुकड़ेंमें फर्क तो होता है। और यह फर्क अुसके प्रति रहे हमारे प्रेम और भावनाओंसे ही पैदा होता है। दुनियामें जो भी भिन्नता देखनेमें आती है वह इसी वजहसे पैदा होती है न? आकार अलग अलग हैं, परन्तु 'अन्तमें तो सब सोना ही है'।

और यदि इस दृष्टिसे देखें तो मनुष्यकी जांच करने पर आखिर क्या रहेगा? 'गन्दी देहका घड़ा' ही न, जिसका नियम है 'जो पैदा हुआ है वह मरेगा ही'। और फिर तो श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुनको दिये गये अुपदेशका भी हवाला दिया जा सकता है।

मुझे लगता है कि इस तरह बात करनेके ढंगमें ही कुछ दोष माना जाना चाहिये। परंतु राजनीतिक रंगमें बातोंकी चर्चा अपने आप ही यह ढंग अस्तित्थार कर लेती होगी।

पटनाके इस कांडकी जांच अब अेक न्यायाधीश कर रहे हैं, इसलिये यहां अुसकी चर्चामें पड़ना जरूरी नहीं है।

२५-९-'५५

म० प्र०

### ध्वज राष्ट्रका या सरकारका ?

राष्ट्रध्वज सारे राष्ट्रका है, न कि उसकी किसी तत्कालीन सरकारका या उसकी पार्टीका। यह दीयेके प्रकाश जैसी वस्तु जब भुला दी जाती है, तब कौसी कमनसीब बातें हो जाती हैं, जिसकी अक मिसाल हालमें दक्षिण भारतमें देखनेको मिली। पाठकोंको यह किस्सा याद होगा।

द्राविड़ संगठनके नेताने हिन्दीके विरोधमें राष्ट्रध्वजको सार्व-जनिक स्थान पर जलानेका निर्णय किया था। परंतु अन्तमें मद्रासके मुख्यमंत्रीके कहनेसे अन्होंने यह विचार छोड़ दिया। क्योंकि, अक मद्रासी मित्रने आंख मटकाकर मुझे कहा कि श्री कामराज नादर भी तो अब्राह्मण ही हैं न ?

यहां मुझे अक अंग्रेजी कविता याद आती है। अमेरिकामें गृह-युद्ध हुआ तब दक्षिण पक्षका सेनापति कूच करता हुआ अक गांवमें दाखिल हुआ। गांवके अक घरके झरोखेमें अमेरिकाका राष्ट्रध्वज लहरा रहा था। दक्षिण पक्षके सेनापतिने हुक्म दिया कि असे गोली मारकर गिरा दो। अतनेमें ही अक वृद्धा स्त्री आकर ध्वजको अुठा लेती है और कहती है, 'यह ध्वज हमारे राष्ट्रका है — आपका भी है। असका अपमान करनेसे पहले आप मेरे प्राण ले लीजिये।' कवि कहता है कि वृद्धाकी यह बात सुनकर सेनापतिको भान आया; असने अपना हुक्म रद्द कर दिया और सेना ध्वजको लहराता हुआ रहने देकर आगे बढ़ गयी।

अस किस्सेमें भी अस सेनापतिने वही भूल की। असने राष्ट्रके ध्वजको अुत्तर पक्षका ध्वज माना — सरकारका ध्वज मान लिया। परंतु अक वृद्धा स्त्रीने अपने प्राणोंकी बाजी लगाकर असकी शान रखी।

अस चीजको कविने अमर कर दिया है। मुझे विचार आता है कि हमारे यहां दक्षिण भारतके या पटनाके किस्से परसे कोअी कविता क्यों न फूटी ?

असका कारण यह तो न हो कि आज भारतमें कवि-हृदय भी राजनीतिक रंगसे बाहर निकलकर अपने कल्पना-व्योममें विहार नहीं कर सकते ? पता नहीं आजादी आनेके बादसे काव्यके पंख अस तरह भारी हो गये हैं या क्या बात है, हमें अस महान् परिवर्तनके संबन्धमें कविगान बहुत कम — नहींवत् सुननेको मिला !

२५-९-५५

म० प्र०

### बम्बयीमें माध्यमकी लड़ायी

सौराष्ट्रके अक प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री काफ़ी व्यंगपूर्ण भाषामें लिखते हैं :

"बम्बयी विश्वविद्यालयने अुच्च शिक्षणकी संस्थाओंमें माध्यम क्या हो, असका विचार करनेके लिये २३ सदस्योंकी अक समिति नियुक्त की है। अब अखबारोंमें समाचार आये हैं कि अिन विद्वान सदस्योंने अपना निर्णय कर लिया है। अस समितिने १९६५ में माध्यम बदलनेकी विश्वविद्यालयमें सिफारिश की है।

"यह निर्णय तो बहुत जल्दीमें किया गया है ! अुच्च शिक्षणमें अितनी तेजीसे परिवर्तन क्यों होना चाहिये ? माध्यम-परिवर्तन पहला परिवर्तन है, और असमें जितनी देर लगे अुतना ही अच्छा है। जल्दीमें कहीं कोअी नुकसान न हो बैठे। माध्यम-परिवर्तनसे अध्यापकोंको भारतकी अेकाध नअी भाषा सीखनी पड़े या मातृभाषामें बोलनेकी आदत डालनी पड़े, यह कितना कठिन काम ? है यह प्रश्न तो जितना टाला जाय अुतना ही ठीक है।

"अिसलिये बम्बयी विश्वविद्यालयको माध्यम बदलनेका विचार १९६५ में नहीं, बल्कि २०६५ में करना चाहिये। सौ वर्षमें बहुतसे प्रश्न अपने-आप हल हो जायंगे। और कौन

जानता है माध्यमका प्रश्न भी अपने-आप हल हो जाय। तब तो विश्वविद्यालयको कोअी चिन्ता नहीं करनी चाहिये। समय जाय, विलम्ब हो, यही ठीक नीति है। परिवर्तन तो करने ही हैं। परंतु जल्दी मचानेसे आखिर क्या होनेवाला है ?

"देश स्वतंत्र हो गया है और नये बल जोर पकड़ते जा रहे हैं, यह चीज पुराणपंथी संस्थाओंके लिये बड़ी कठिनायी पैदा कर रही है। ताजी हवा अन्दर घुसनेके लिये हमला कर रही है और अन्दरके लोगोंकी सारी शक्ति मानो हवाको भीतर न आने देनेके लिये खिड़की-दरवाजे बन्द रखनेमें ही खर्च हो रही है।"

यह सच है कि बम्बयी विश्वविद्यालय माध्यमके प्रश्नके संबन्धमें बहुत देरसे जागा है, परंतु यह उसके बुढ़ापेका दोष नहीं माना जा सकता। क्योंकि नया और अद्यतन माना जानेवाला बुढ़ोदा विश्व-विद्यालय भी अस संबन्धमें अभी कहां विचार करने लगा है ? फिर भी बम्बयीने अक बातका निर्णय तो कर लिया है कि अंग्रेजी माध्यम नहीं रहेगा। कुछ लोग अभी भी असे रखनेके पक्षमें हैं, लेकिन विकल्पके तौर पर। बम्बयी, मद्रास और कलकत्ता जैसे हमारे सबसे पुराने विश्वविद्यालयोंमें अंग्रेजी समान रूपसे गले पड़ी लगती है ! तीनों जगह असे कायम रखनेके मिथ्या प्रयत्न किये जा रहे हैं।

अब जब अंग्रेजीका जारी रहना संभव नहीं है, तो मद्रासने कहा कि अंग्रेजीकी जगह कभी न कभी तामिल आयेगी; मैं मानता हूं कि कलकत्ता बंगालीकी ही बात कहेगा, परंतु बम्बयी तो अनोखी और अलबेली नगरी ठहरी। वहां आन्तरभाषा हिन्दीको माध्यम बनानेकी बात चल रही है। तो क्या मद्रास और कलकत्तेमें पचरंगी आबादी नहीं होगी ? और बम्बयीमें अैसी कौनसी पचरंगी आबादी है ? कॉलेजमें पढ़नेवाले विद्यार्थियोंके प्राप्त आंकड़ों परसे पता चलता है कि वहां कुल पचीस हजारमेंसे ९-१० हजार महाराष्ट्री, ८-९ हजार गुजराती और बाकी अन्य भाषा-भाषी विद्यार्थी हैं। अससे तो स्पष्ट हो जाता है कि वहां मराठी और गुजरातीको माध्यमका स्थान मिलना ही चाहिये। अससे अिनकार करना भारतीय संविधानका द्रोह करना है।

अब बम्बयीमें माध्यमका युद्ध शुरू हुआ है। आशा रखें कि अन्तमें वह अस सीधीसादी बात पर आकर शान्त होगा। माध्यम परिवर्तन हमारे शिक्षण-सुधारकी पहली सीढ़ी है। हमें समझ लेना चाहिये कि जब तक यह प्रश्न सही ढंगसे हल नहीं होगा, तब तक शिक्षणका सारा काम सच्चे रास्ते पर नहीं चलेगा।

२३-९-५५

(गुजरातीसे)

म० प्र०

### बापूकी झांकियां

[संशोधित आवृत्ति]

लेखक : काका कालेलकर

कीमत १-०-०

डाकखर्च ०-५-०

नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद-१४

विषय-सूची	पृष्ठ
भारतका समाजशास्त्र	विनोबा ३०५
समान भाषा और प्रजाभावना	मगनभाई देसाई ३०६
चर्म-अुद्योगका विकास	वि० ३०७
राजभाषा कमीशन	मगनभाई देसाई ३०८
लोकशाही और निष्णातशाही	मगनभाई देसाई ३०९
विविध विचार	म० प्र० ३१०
टिप्पणी :	
जीवन और संहारका स्तर	म० प्र० ३०९